दिव्यांगों को मिलेगा यूडीआईडी नंबर, देशभर में होगा मान्य

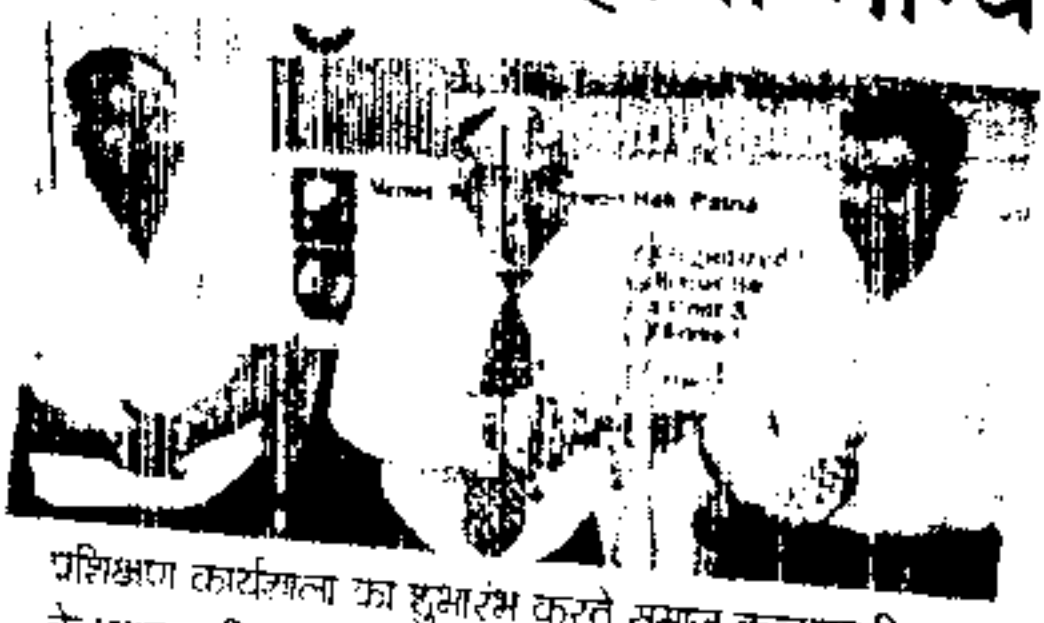

प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ करते समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद, केवीएस राव व अन्य।

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं। अब उन्हें डिसएबिलिटी आइडेन्टिटी कार्यक्रम (यूडीआईडी) के तहत एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, जो पूरे देश में मान्य होगा। इस परियोजना की शुरुआत दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई है। इसमें राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग की भी सक्रिय भूमिका है। राज्य में यूडीआईडी की तैयारी के लिए यहां नियोजन भवन में दोनों विभागों ने संयुक्त रूप से शनिवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया।

पहचान भी, सम्मान भी

समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने कहा कि दिव्यांगों को यूनिक आईडी से पहचान और सम्मान दोनों मिलेगा। यह एक सरकारी दस्तावेज है। यह उनके सशक्तीकरण का माध्यम है। इस परियोजना के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध आंकड़े दिव्यांगों के हित समाज के हर वर्ग के लिए उपयोगी होगा। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए पदाधिकारियों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। प्रयास यह होना चाहिए कि लाभार्थियों को तय समय सीमा के अंदर इन सेवाओं को लाभ मिल सके। कार्यशाला में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी रमाशंकर प्रसाद एसआर ने कहा कि दिव्यांगों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो, उसके लिए ही केंद्र सरकार ने यूडीआईडी योजना शुरू की है।

माउस के एक क्लिक पर मिलेगी सूचना

केंद्र सरकार की यूडीआईडी परियोजना के निदेशक केवीएस राव ने कहा कि यह सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित योजना है। दिव्यांगों के बारे में सभी जानकारी माउस के एक क्लिक पर मिल जाएगी। इससे निर्णय लेने में मदद मिलेगी। दिव्यांग जनों की कुछ श्रेणियां अभी तक उपेक्षित रही हैं, लेकिन अब हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। नई व्यवस्था के तहत प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता का यूडीआईडी का नंबर डालकर पता किया सकेगा। मौके पर राज्य स्वास्थ्य समिति के सचिव शशि भूषण कुमार, यूडीआईडी के संजय भास्कर, सक्षम के केके मिश्रा और पटना प्रमंडल के सभी जिलों के ...